भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2538

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लखपति दीदी लाभार्थी

2538. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बजट 2025-26 में घोषित 2027 तक तीन करोड़ के लक्ष्य के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) से संबंधित और लखपति दीदी के रूप में नामित महिलाओं की संख्या का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने वर्तमान 1.25 करोड़ महिला लाभार्थियों में एससी/एसटी के विशेष रूप से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुपात का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो दलित और आदिवासी महिलाओं को कथित तौर पर स्वयं सहायता समूहों और ड्रोन दीदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अलग रखने वाले राज्यों के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) लखपति दीदी, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएम) की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें कम से कम 4 कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों के लिए स्थायी आधार पर एक लाख रुपये प्रति वर्ष की न्यूनतम आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। 31.12.2024 तक, कुल लखपति दीदियों में से 21.45%

अनुसूचित जाति श्रेणी की हैं, 14.18% अनुसूचित जनजाति श्रेणी की हैं, और 42.89% अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित हैं।

(ख) और (ग) एनआरएलएम के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित कमजोर समुदायों की महिलाओं को राज्यों के साथ समन्वय से एसएचजी में संगठित किया जाता है। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लक्ष्य समूह लक्षित समुदायों के सदस्यों को जोड़ते हुए गरीबों (पीआईपी) की भागीदारी का चयन एक सुपरिभाषित, पारदर्शी और न्यायसंगत प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। पीआईपी प्रक्रिया के माध्यम से गरीब चिन्हित किए गए सभी परिवार, जिनमें कम से कम एक वंचना वाले परिवार भी शामिल हैं उनका डेटा ग्राम सभा के सामने सत्यापन के लिए पेश किया जाता है और बाद में ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इस तरह वे डीएवाई-एनआरएलएम लक्ष्य समूह परिवार बन जाते हैं और कार्यक्रम के तहत सभी लाभों के लिए पात्र होते हैं।

राज्य मिशनों को डीएवाई-एनआरएलएम गहन गतिविधियों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। डीएवाई-एनआरएलएम के लिए सामाजिक प्रबंधन ढांचा (एसएमएफ) सामाजिक समावेशन, सामाजिक जवाबदेही और सामाजिक सुरक्षा उपायों पर केंद्रित है जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) सहित हाशिए पर और कमजोर सामाजिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करने तथा बेहतर आजीविकाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके वित्तीय एवं आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के मार्गदर्शन के लिए सामाजिक समावेशन योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

"नमो ड्रोन दीदी" दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएलएफ/राज्य स्तरीय समिति एक सक्रिय एसएचजी सदस्य को प्रशिक्षित करने और ड्रोन पायलट के रूप में नामित करने के लिए चिन्हित करती है।

*****